

न्यायालय थींगानु राजस्व मुँडल पांडीगार जिला गढ़वाल १०८.प्र.०३

ग्रामपाली/ठीकमगढ़/भूतरा/२०१७/६५७

द्वारा आज दि. १८/११/१८ तक उत्तराखण्ड के लिए बड़ागांव जिला टीकमगढ़ में प्रस्तुत! दिनांक १८/११/१८ वर्षात् अपने को बड़ागांव जिला टीकमगढ़ में राजस्व भूमि का बोलता है।

पिल कुमार तनय दोट लाल जैन निवासी बुड़ेरा
द्वारा बड़ागांव जिला टीकमगढ़ १०८.प्र.०३
... निगरानीकार

बनाम

बिदू तनय केवर मुहम्मद निवासी बुड़ेरा तहसील
बड़ागांव जिला टीकमगढ़ १०८.प्र.०३
... उत्तरवादी

आधेदन पत्र अंतर्गत धारा-५० न.प्र.भू.रा.सं. १९५९

महत्व

प्रतिकूल आदेश राजस्व निरीक्षक बड़ागांव धान तहसील बड़ागांव जिला
टीकमगढ़ म.प्र. के प्रकरण ५ मांक-१४/३-१२/१६-१७ में पारित आदेश दिनांक
२६. ११. २०१८ के विरुद्ध

महोदय,

निगरानीकार की चियावाद पर निम्न प्रकार है:-

१। यह कि राजस्व निरीक्षक बड़ागांव धान तहसील पारित सीमांकन आदेश

विधि के सापेक्ष नहीं होने के कारण निरती योग्य है।

२। यह कि सीमांकन आदेश में लेख किया गया है कि भूमि खंसरा नम्बर-

८१६/१ स्थित ग्राम के अंश भाग पर निगरानीकार का ५०४४ व नींव स्वं

दीवाल बनाकर अैथ कड़ा पाया गया तरन्तु उनके द्वारा पारित इस आदेश में

रकवा का हवाला नहीं दिया गया कि वित्ते रकवा पर नींव खोदकर स्वं दीवाल

बनाकर निगरानीकार द्वारा अैथ कड़ा किया गया है। इस तरह राजस्व निरीक्षक

कासीमांकन आदेश बोलता है कि हीं होने के कारण निरती योग्य है।

३। यह कि उपरोक्त सीमांकन में न तो कोई पंचामा बनाकर संलग्न किया

गया स्वं न ही किसी भी पक्षकार द्वारा कार्यवाही के संदर्भ में दत्ताधरित किया

गया। जिसे यह साफ प्रतीत होता है कि सीमांकन की कार्यवाही न तो मौके पर

मई और न ही विधिवत् की गई। जिसे उक्त आदेश की तरी योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रेण क्रमांक :—एक / निगरानी / टीकमगढ़ / भू.रा./ 2017 / 6157

जीवन कुमार विरुद्ध छिद्दू

रथान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों ए अभिभाषकों हस्ताक्षर
12-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से श्री दिवाकर दीक्षिक अभिभाषक उपस्थित ।</p> <p>3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक बड़ागांव धसान तहसील बड़ागांव, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 14 / अ-12 / 2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 26-11-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 08-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p> 	<p>(आर.क. जैन) ३१३११९</p> <p>संबस्य</p>